

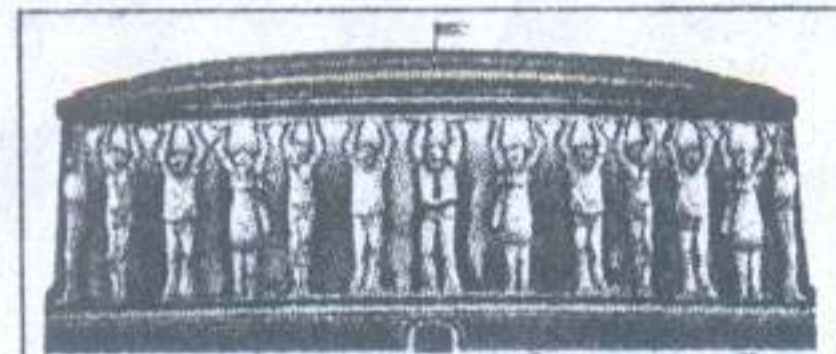
पर्यावरण संबंधी नीति में सहभागी का साथ जरूरी

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

पर्यावरण में हो रहे बदलाव और पानी की समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि सरकार, विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन और आम जनता मिलकर काम करें। इनसे संबंधित जो भी नीतियां बनाई जाएं उसमें सभी की सहभागिता हो ताकि नीतियों के बाद में कोई खामियां न निकलें और देश का विकास सही दिशा में जाए। ये विचार मंगलवार को टाइम्स हाउस में पर्यावरण से संबंधित विषय पर आयोजित टाइम्स ऑफ इंडिया के अभियान सहभागी की बैठक में निकल कर सामने आए।

बैठक की अध्यक्षता बीसीसीएल की चेयरपर्सन इंदु जैन ने की। बैठक में जानी-मानी पर्यावरण विशेषज्ञ वंदना शिवा, जल बिरादरी से अरुण तिवारी, सेंटर फॉर एनवॉयरमेंट की किरण, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से तृप्ता धवन व नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर चंद्रशेखर प्राण सहित कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सहभागी जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करेगी। बैठक में इंदु जैन ने कहा कि एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन उनका दायरा सीमित है। अगर इसमें सरकार की सहभागिता जुड़ जाए और सब एक साथ मिलकर काम करें तो निश्चित तौर पर हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बैठक में वंदना शिवा ने सुझाव दिया कि पर्यावरण में आए बदलाव के कारण पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है,

कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है। ऐसे में एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाए जाने की जरूरत है। इसमें सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठन, समुदाय, विशेषज्ञ की भी राय ली जाए। बदलते मौसम की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि वे अलर्ट हो जाएं। सेंटर फॉर एनवॉयरमेंट की ओर से विशेषज्ञ किरण ने सुझाव दिया कि पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी एक वेबसाइट के



NBT साप्टोर्ट्स
सहभागी
नागरिकों की भागीदारी,
हर नेता की जिम्मेदारी

जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए। नेहरू युवा केंद्र के निदेशक चंद्रशेखर प्राण का कहना था कि कोई भी नीति बनाते वक्त जब विचार-विमर्श होता है तो विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जब पॉलिसी का निर्णय होता है तो नौकरशाह शामिल होते हैं। लेकिन, हर स्तर पर लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। बैठक में जैव विविधता के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। इसे ग्राम पंचायतों के जरिए लागू किए जाने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों की सहभागिता पर भी जोर दिया गया।